श्रीमति शन्नो देवी

बनाम

मंगल सेन

[एस- के- दास एम- हिदायतुल्ला- के- सी- दास गुप्ता] जे- सी- शाह और एन- राजगोपाला अय्यर] न्यायामूर्तिगण]

भारत के प्रवासन,- नागरिकता, स्थाई निवास के आशय-के लिये दावा,-चुनावी विवाद-"भारत के राज्य क्षेत्र में चले गये' , "साधारण निवासी" भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 का अर्थ।

प्रत्यर्थी पंजाब विधानसभा के लिये मार्च 1957 में हुए आम चुनावों का एक सफल उम्मीदवार था। अपीलार्थी, जो असफल उम्मीदवारों में से एक था, ने एक चुनाव याचिका दायर की और प्रत्यर्थी के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी कि वह बाद में भारत का नागरिक नहीं था और इसलिये वह बाद में भारत का नागरिक नहीं था और इसलिये वह चुनाव में खडे होने योग्य नहीं था। यह पाया गया कि उसका जन्म 1927 के आस पास भारतीय माता-पिता से] भारत सरकार, अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत के किसी गांव में हुआ था जो कि 15 अगस्त 1947 से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। यह कि 1944 से पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। यह कि 1944 से वह अपने गृह जिले से जालन्धर चले गये थे, जो कि अब भारत का राज्य क्षैत्र है, और 15 अगस्त 1947 के

पश्चात् उन्होने स्थाई रूप से भारत में निवास करने का मन

बना लिया है। यह दिखाने के लिये कुछ सबूत थे, कि वह जनवरी 1950 में बर्मा गया था और बर्मा सरकार से वह स्थाई रूप से रहने के लिये अनुमति प्राप्त करने के असफल प्रयास किये थे।

प्रतिपादित किया गया (1) कि अभिव्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवासन'' का भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अर्थ में भारत के संविधान के लागू होने से पूर्व किसी समय भारत के राज्य क्षैत्र में किसी स्थान पर प्रवास है।''

(2) यह कि अनुच्छेद में शब्द ''भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवासन'' का अर्थ ''भारत के राज्य क्षैत्र में स्थाई रूप से निवास करने के आशय से आना है।

(3) यह कि जहां कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में अस्थाई रूप से रहने के आशय से जाता है, और बाद में उसका वहां स्थाई रूप से बसने का मन बन जाता है, तो उसे कानूनी तौर पर सही समय पर उस देश में प्रवासित माना जाना चाहिऐ।

(4) अनुच्छेद 6 (बी)(प) के तहत् ''उसके प्रवास की तारीख से भारत के राज्य क्षैत्र में सामान्यता निवासी होने' का परीक्षण लागू करने के लिये यह आवश्यक है कि उस अवधि के दौरान, जिस दिन प्रवास प्रांरभ हुआ और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। सम्पूर्ण रूप से वह व्यक्ति भारत

के राज्य क्षेत्र का सामान्य निवासी रहा है। 26 जनवरी 1950 को वह

भारत में नहीं था, जनवरी 1950 में जब से बर्मा के लिये रवाना हुए तो क्या उन्होने वहां अपना स्थाई निवास बनाने का इरादा बनाया था, यह प्रासंगिक नहीं है।

दीवानी अपीलीय अधिकारिताः- सिविल अपील सं.- 247 सन 1960

पजांब उच्च न्यायालय की प्रथम अपील सं. 131 सन 1958 में दिनांक 3 अक्टुबर 1958 को पारित निर्णय एवं आदेश से अपील।

ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री और नौनित लाल,-अपीलार्थी की ओर से।

यू. एम. त्रिवेदी और गणपत राम,- प्रत्यर्थी की ओर से।

7 सितम्बर 1960- न्यायालय का निणर्य न्यायमूर्ति दास गुप्ता द्वारा दिया गया-

संविधान के अनुच्छेद 6 में उल्लेखित शब्द ''भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवासन'' का क्या अर्थ है, यही इस अपील में मुख्य प्रश्न है। अपीलकर्ता, शन्नो देवी, पंजाब विधानसभा के लिये मार्च 1957 में हुए आम चुनावों में असफल उम्मीदवारों में से एक थी। प्रतिवादी, मंगल सेन, सफल उम्मीदवार थे। इन और अन्य उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की जांच 1 फरवरी, 1957 को की गई, जो उसी तिथि को स्वीकार कर लिए गए। 12 मार्च को मतदान हुआ और 14 मार्च 1957 को वोटों की गिनती के बाद प्रतिवादी मंगल सेन को विधिवत निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 27 मार्च, 1957

को, अपीलकर्ता ने एक चुनाव याचिका दायर की और विभिन्न

आधारों पर प्रतिवादी के चुनाव को चुनौती दी, मुख्य आधार यह था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रतिवादी के नामांकन पत्र को इस आधार पर अनुचित तरीके से स्वीकार कर लिया था जबकि वह भारत का नागरिक नहीं था और चुनाव में खड़े होने के योग्य नहीं था। इस याचिका में लिए गए अन्य आधारों से हमें अब कोई सरोकार नहीं है क्योंकि चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा इन कई आधारों को खारिज करने के बाद उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था और हमारे सामने भी नहीं उठाया गया है। हालाँकि, चुनाव न्यायाधिकरण ने माना कि मंगल सेन उस समय भारतीय नागरिक नहीं थे जब उन्हें मतदाता के रूप में नामांकित किया गया था या जब उनका नामांकन पत्र स्वीकार किया गया था और यहाँ तक कि उस समय भी जब वे निर्वाचित हुए थे। तदनुसार, ट्रिब्यूनल ने चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादी के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया। मंगल सेन द्वारा उच्च न्यायालय में अपील में एकमात्र मुद्दा यह उठाया गया कि क्या अपीलकर्ता संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक था। यदि वह ऐसे प्रारंभ की तिथि पर भारत का नागरिक था, तो इसमें कोई विवाद नहीं था, वह सभी प्रासंगिक तिथियों पर भारत का नागरिक बना रहा, जैसे कि मतदाता के रूप में उसके नामांकन की तिथि, उसकी स्वीकृति की तिथि। नामांकन और उसके चुनाव की तारीख। हालाँकि, यदि वह संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक नहीं था, तो उसने तब से नागरिकता हासिल नहीं की है और इसलिए उसका चुनाव शून्य होगा। प्रतिवादी का मामला

हमेशा यह था कि वह अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक था। संविधान के अनुच्छेद 5 और इसके अलावा अनुच्छेद 6 के तहत ऐसे प्रारंभ पर उसे भारत का नागरिक माना जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 6 जैसा कि पहले ही संकेत दिया जा चुका है, चुनाव न्यायाधिकरण ने इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने संकेत देते हुए कहा कि वे यह सोचने के इच्छुक थे कि प्रतिवादी का भारत की नागरिकता का दावा अनुच्छेद 6 के तहत है। अनुच्छेद 5 कायम नहीं रखा जा सका, उन्होंने उस मामले पर विस्तार से विचार नहीं किया, लेकिन यह माना कि संविधान के प्रारंभ में अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक माने जाने का उनका दावा प्रबल होना चाहिए, ट्रिब्यूनल द्वारा अपने समक्ष पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्यों पर पाए गए प्राथमिक तथ्यों को उच्च न्यायालय के फैसले में इन शब्दों में सही ढंग से संक्षेपित किया गया हैः-

"पक्षों के द्वारा दिये सबूतों पर विद्वान न्यायाधिकरण ने माना कि यह साबित हो गया है कि मंगल सेन का जन्म 1927 में सरगोधा जिले के झवारियां गांव में भारतीय माता-पिता से हुआ था, और जब वह केवल दो साल का था, तो उसके माता-पिता उसे ले गए थे। झवारियां से बर्मा के मांडले, जहां से पूरा परिवार 1942 में जालंधर (पंजाब) लौट आया, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा पर जापानी सेना ने कब्जा कर लिया

था। जालंधर में कुछ दिनों तक रहने के बाद, मंगल सेन, उनके

माता-पिता और उनके भाई अपने गृह जिले सरगोधा में चले गए। जहां वे लगभग दो या ढाई साल तक रहे। इस अवधि के दौरान मंगल सेन ने पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और मैट्रिक पास करने के बाद वे फिर से जालंधर लौट आए, जहां वे फिल्ड मिलिट्री अकाउंट्स में कार्यरत थे। 8 दिसंबर, 1944 से 7 अगस्त, 1946 तक कार्यालय, जब ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। विद्वान न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के अनुसार मंगल सेन के माता-पिता और उनके भाई भी सरगोधा से जालंधर लौट आए और लगभग वहां रहे 1945 के कुछ समय बाद से ढाई साल पहले वे फिर से बर्मा चले गए, जिस देश पर 1942 में जापानी सेना के कब्जे के कारण उन्होंने बर्मा छोड़ दिया था। जब मंगल सेन फील्ड सैन्य लेखा कार्यालय में सेवा में थे, तब वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आंदोलन में शामिल हो गए और इसके सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। उनकी सेवाएँ समाप्त होने के कुछ समय बाद, उन्होंने अपनी गतिविधियाँ हिसार और रोहतक जिलों में स्थानांतरित कर दीं, जहाँ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आंदोलन को संगठित करने के लिए उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। इस अवधि के दौरान जाहिर तौर पर उनका कोई निश्चित निवास स्थान नहीं था और वे जनसंघ के कार्यालयों में रहते थे और विभिन्न ढाबों में भोजन करते थे। वर्ष 1948 में जून से सितम्बर तक लगभग 4 माह तक मंगल सेन ने आर्य लोअर मिडिल स्कूल, रोहतक में अध्यापक के रूप में कार्य किया। जुलाई 1948 में

मंगल सेन ने यूनिवर्सिटी प्रभाकर परीक्षा के लिए अपना प्रवेश फॉर्म पंजाब विश्वविद्यालय में जमा किया, जिसे गवर्नमेंट कॉलेज, रोहतक के प्रोफेसर कांशी राम नारंग द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया था। जनवरी 1949 में किसी समय उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आंदोलन के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया और 10 जनवरी, 1949 से 30 मई, 1949 तक रोहतक जिला जेल में हिरासत में रखा गया। अगस्त 1949 में वे फिर से प्रभाकर परीक्षा में उपस्थित हुए और उन्हें कंपार्टमेंट में रखा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 1948-49 के दौरान रोहतक और हिसार जिलों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आयोजन किया था और वे बिना किसी निश्चित निवास स्थान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ट्रिब्यूनल ने आगे पाया कि 1949 के अंत में या जनवरी 1950 में किसी समय मंगल सेन ने भारत छोड़ दिया और बर्मा चले गए जहाँ उनके माता-पिता और अन्य भाई पहले से ही रह रहे थे। उस देश में उन्होंने स्थायी रूप से रहने की अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन बर्मा सरकार सहमत नहीं हुई और उन्हें वह देश छोड़ने का निर्देश दिया। इस संबंध में उन्होंने बर्मा के सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट के लिए आवेदन किया, लेकिन उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई। 29 अक्टूबर, 1951 को, मंगल सेन ने विदेशियों के पंजीकरण अधिनियम, 1948 के तहत उन्हें दिए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र को बर्मा में सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर दिया और कुछ दिनों बाद वह भारत वापस आ गए और तब से वह यहीं

रह रहे हैं। देश और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिसार और रोहतक जिलों में आंदोलन का आयोजन कर रहा है। 1953 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 8 फरवरी से 8 मई, 1953 तक एक बंदी के रूप में रोहतक जेल में रखा गया, जब उन्हें अंबाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।

इन तथ्यों पर ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि ''प्रतिवादी का भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा था और उसका इसे कभी भी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था । इन तथ्यों को साथ लेते हुए प्रतिवादी की हलफनामे में घोषणा (उदाहरण 5) जिसे हम वर्तमान में संदर्भित करेंगे, ट्रिब्यूनल ने आगे कहा कि ''हलफनामे में उसकी अपनी घोषणा (उदाहरण 5) और बर्मा जाने और प्रयास करने में उसका आचरण वहां स्थायी रूप से बसने का यह पुख्ता सबूत पेश करें कि उसका हमेशा से अपने माता-पिता और अन्य रिश्तेदारों के साथ बर्मा जाने और वहां स्थायी रूप से बसने का इरादा था।'' ट्रिब्यूनल ने अंततः यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि, यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रतिवादी के मामले में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके पास किसी निश्चित या अनिश्चित घटना की प्रतीक्षा किए बिना भारत में बने रहने के अलावा कोई अन्य विचार नहीं था जो उसे प्रेरित कर सके। अपना निवास स्थान बदलने के लिए तथ्य के

इन निष्कर्षों पर ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रतिवादी को संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है।

ऊपर उल्लेखित इन्हीं प्राथमिक तथ्यों पर, उच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय देने वाले श्री न्यायमूर्ति दुआ ने अपना निष्कर्ष इस प्रकार दर्ज कियाः-

> "मैं रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों से केवल एक निष्कर्ष निकाल सकता हूं, कि अपीलकर्ता जो अपने गृह जिले से जालंधर चला गया था, उसका 15 अगस्त, 1947 के बाद, भारत के डोमिनियन को अपना निवास स्थान बनाने के अलावा कोई अन्य इरादा नहीं था। 15 अगस्त, 1947 को, इसलिए अपीलकर्ता का झवारियां से भारत के क्षेत्र में प्रवास स्पष्ट रूप से पूरा हो गया था, उस तारीख से पहले जो भी संदेह हो, मैं यह मानने के लिए भी तैयार हूं कि वह अपने गांव से दूर चला गया था, 1944 में और पंजाब के पूर्वी जिलों में चले गए थे" ।

श्री न्यायमूर्ति फाल्शॉ इस निष्कर्ष से सहमत थे। इन निष्कर्षों पर विद्वान न्यायाधीशों ने माना कि प्रतिवादी का संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक समझे जाने का दावा सफल होना चाहिए। अपीलकर्ता की ओर से मुख्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष, कि जब प्रतिवादी

1944 में अपने गांव से दूर चला गया और 15 अगस्त, 1947 के बाद किसी भी दर पर, उसका ऐसा करने के अलावा कोई अन्य इरादा नहीं

था। उनके निवास स्थान भारत पर प्रभुत्व मनमाना था। यह भी तर्क दिया गया कि प्रवासन के किसी भी मामले में संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार'' '' ,
अस्तित्व में आ गया है। अंततः यह तर्क दिया गया, हालांकि हल्का सा, कि प्रतिवादी ने किसी भी मामले में अपने प्रवास की तारीख के बाद से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होने की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया है। प्रतिवादी के वकील ने उपरोक्त तर्क की सत्यता को चुनौती देने के अलावा यह भी आग्रह किया कि अनुच्छेद 6 में ''भारत के क्षेत्र में प्रवासन'' शब्द का अर्थ केवल भारत के क्षेत्र में आना है ''और इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने के इरादे से आना''।

अपीलकर्ता की ओर से श्री शास्त्री द्वारा उठाया गया चरम विवाद यह है कि अनुच्छेद 6 के तहत प्रवासन को संविधान के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के अस्तित्व में आने के बाद घटित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बात पर ध्यान देना होगा कि अनुच्छेद 6 इस प्रश्न से संबंधित है कि संविधान के प्रारंभ में किसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यह स्वयं सुझाव देता है, विपरीत इरादे को इंगित करने वाली किसी भी चीज के अभाव में, कि प्रवासन जिसे इस उद्देश्य के लिए एक आवश्यक आवश्यकता बनाया गया है, ऐसे प्रारंभ से पहले हुआ होगा। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अनुच्छेद 6 का खण्ड बी जिसमें दो शर्तों का उल्लेख

है, जिनमें से एक को जन्म के अतिरिक्त पूरा किया जाना चाहिए जैसा कि उपखण्ड ए में उल्लेखित है और ''प्रवासन'' जैसा कि अनुच्छेद के मुख्य भाग में उल्लेखित है, साबित हो रहा है, इसके पहले उपखण्ड ए में कहता है। प्रवासन की ''जुलाई 1948 के 19 वें दिन से पहले' और उपखण्ड (ii) में प्रवासन ''19 जुलाई 1948 के बा''

व्यक्ति को संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को दिए गए आवेदन पर भारत डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। उस अनुच्छेद के प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम छह महीने तक भारत के क्षेत्र में निवासी न रहा हो। इससे स्पष्ट है कि अनुच्छेद 6 में प्रवासन का कार्य संविधान के प्रारंभ होने से पहले होना चाहिए। इसलिए यह स्पष्ट है कि ''भारत के क्षेत्र में प्रवासित'' का अर्थ है ''संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय भारत के क्षेत्र में किसी स्थान पर प्रवासित''।

यह हमें इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है कि क्या भारत के क्षेत्र में प्रवासन का अर्थ है ''केवल भारत के क्षेत्र में आना' या इसका अर्थ है ''यहां रहने के लिए भारत के क्षेत्र में आना' या दूसरे शब्दों में, ''भारत के क्षेत्र में आना'', यहाँ स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से' आना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माइग्रेट शब्द ''अपने आप में व्यापक निर्माण में

सक्षम हैं' एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना ''चाहे बाद वाले स्थान पर स्थायी निवास के किसी इरादे से हो या नहीं। यह विवाद से परे है कि'' माइग्रेट शब्द ''एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना'' का उपयोग अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से आना'' के संकीर्ण अर्थ में भी किया जाता है। वेबस्टर डिक्शनरी (द्वितीय संस्करण, 1937) ''माइग्रेट'' शब्द का निम्नलिखित अर्थ देता हैः- ''एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना विशेष रूप से, निवास की दृष्टि से एक देश, क्षेत्र या निवास स्थान से दूसरे देश में जाना या प्रवास करना, हिलना, डुलना। मूर्स के रूप में जो अफ्रीका से स्पेन चले गए। 1948 में प्रकाशित कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम का अर्थ वही है, सिवाय इसके कि यह ''किसी के निवास स्थान को बदलने' को भी एक अर्थ के रूप में देता है। ''इमिग्रेट'' शब्द का अर्थ है ''स्थानांतरित करना' एक देश में' और इसके व्युत्पन्न ''आप्रवासी' और ''आव्रजन'' को आप्रवासन कानूनों के उल्लंघन के लिए अभियोजन के संबंध में कई ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मामलों में न्यायिक विचार प्राप्त हुआ है।

ऑस्ट्रेलिया में न्यायालयों की अपने कानूनों की योजना और विषय-वस्तु पर विचार करने पर यह राय थी कि अप्रवासी पंजीकरण अधिनियम, 1901 और धारा में ''आप्रवासी' शब्द। ऑस्ट्रेलियाई संविधान के 51 का

अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो ऑस्ट्रेलिया में बसने और रहने के इरादे से प्रवेश करता है या नहीं (वीडियो चिया जी बनाम मार्टिन (1) हालाँकि,

अमेरिकी अदालतों ने संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम बर्क (2), मोफिट बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका (3) और संयुक्त राज्य बनाम अटलांटिक फ्रूट कंपनी (4) में कानून के उद्देश्य और योजना पर विचार करते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया कि ''आप्रवासी का अर्थ वह व्यक्ति है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थायी रूप से निवास करने के उद्देश्य से आता है।

हमने ''आव्रजन'' शब्द के अर्थ पर इन मामलों का उल्लेख यह दिखाने के लिए किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कुछ संदर्भों में ''प्रवासन'' शब्द का व्यापक अर्थ ''आओ या हटाओ'' हो सकता है

(1) (1905) 3 सीएलआर 649

(2) (1899) 99 संघीय रिपोर्ट 895

(3) (1904) 128 संघीय रिपोर्ट 375

(4) (1914) 212 संघीय रिपोर्ट 711

''स्थायी रूप से निवास करने के इरादे के बिना स्थान'' और कुछ संदर्भ में, संकीर्ण अर्थ ''स्थायी रूप से रहने के इरादे से किसी स्थान पर आना या जान' '। तथ्य यह है कि संविधान निर्माताओं ने''निवास करने के इरादे से'' शब्दों का उपयोग नहीं किया था। हालाँकि, अनुच्छेद 6 में स्थायी रूप से ''यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि व्यापक अर्थ का इरादा था। यह तय करने में कि क्या' माइग्रेट ''शब्द का उपयोग व्यापक या संकीर्ण अर्थ में किया गया था, इस संवैधानिक विधायन के उद्देश्य और योजना पर

सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक है। संविधान अपने पहले अध्याय में शामिल चार अनुच्छेदों में भारत के क्षेत्र को परिभाषित करने और इसे कैसे जोड़ा या बदला जा सकता है, इसके प्रावधान करने के बाद दूसरे अध्याय में नागरिकता के विषय से निपटने के लिए आगे बढ़ता है। सात अनुच्छेदों में से इस अध्याय में अंतिम अनुच्छेद, 11, केवल नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करने के संसद के अधिकार को स्पष्ट रूप से बचाता है। अन्य छह लेखों में से पहला, अनुच्छेद 5, कहता है कि संविधान के प्रारंभ में भारत का नागरिक कौन हो गया, जबकि अनुच्छेद 6 और 8 उन लोगों को निर्धारित करते हैं जो हालांकि अनुच्छेद 5 के तहत नागरिक नहीं हैं, भारत का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 10 में प्रावधान है कि एक बार जब कोई व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाता है या उसे भारत का नागरिक मान लिया जाता है तो वह संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन, भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 7 कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार से भी वंचित करता है जो अन्यथा अनुच्छेद 5 के तहत भारत के नागरिक होते। अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक माना जाएगा।

इस योजना में भारत की नागरिकता के लिए प्राथमिक प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। यह जन्म या अधिवास पर जोर देने की सामान्य प्रथा का अनुसरण करता है, जिसका शीघ्र ही अर्थ नागरिकता के लिए एक आवश्यक आवश्यकता के रूप में ''देश में रहने और मरने के इरादे से निवास'' बताया गया है और इस आवश्यकता को पूरा करने वाले व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करता है यदि वह वर्तमान भारत के क्षेत्र के भीतर अपने जन्म या इस क्षेत्र के भीतर अपने माता-पिता में से किसी के जन्म या इस क्षेत्र में लगातार पांच साल की अवधि के लिए सामान्य निवास के संबंध में एक अन्य आवश्यकता को भी पूरा करता है। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले'', यदि भारत का कोई विभाजन नहीं हुआ होता और पुराने भारत का कोई भी हिस्सा खो नहीं गया होता, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को ऐसे अधिकार देने के विशेष प्रावधान के अलावा नागरिकता प्रदान करने के संबंध में यह पर्याप्त होता। लेकिन भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित भारत का एक हिस्सा अब भारत नहीं रहा और पाकिस्तान बन गया। इससे यह गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई कि उन लाखों व्यक्तियों को, जो भारतीय मूल के थे, भारत का नागरिक माना जाए या नहीं, इस अर्थ में कि उनका या उनके माता-पिता या उनके दादा-दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ था। लेकिन कौन, अनुच्छेद 5 के तहत नागरिक नहीं बनेगा। संविधान-निर्माता अनुच्छेद 6 के प्रावधानों द्वारा इनमें से कुछ को नागरिक मानने का निर्णय लिया, लेकिन सभी को

नहीं जो लोग संविधान के लागू होने की तारीख से पहले नए भारत में नहीं आए थे, उन्हें बाहर रखा गया जो लोग आए थे उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, - वे जो 19 जुलाई, 1948 से पहले आए थे, और वे जो 19 जुलाई, 1948 को या उसके बाद आए थे। पहली श्रेणी के व्यक्तियों को नागरिक माना जाना था। ''प्रवासन'' की आगे की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, चाहे इसका कोई भी अर्थ हो, और भारत में उनके ''प्रवासन'' के बाद से भारत के क्षेत्र में सामान्य निवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिये जबकि दूसरी श्रेणी के लोगों को, प्रवासित होने के अलावा, नागरिकों के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन की तारीख से कम से कम छह महीने पहले तक निवासी होना था, जिसके लिए आवेदन संविधान के प्रारंभ की तारीख से पहले दायर किया जाना था। लेकिन जबकि संविधान में प्राथमिक प्रावधान उन लोगों के लिए नागरिकता के संबंध में हैं जिनका जन्म अब भारत में शामिल किसी स्थान पर हुआ है और जिन लोगों के माता-पिता अब भारत में किसी स्थान पर पैदा हुए हैं, वे ''अधिवास'' शब्द का उपयोग करके यहां स्थायी रूप से निवास करने के इरादे की आवश्यकता पर जोर देते हैं। ''अनुच्छेद 6 जो संविधान की योजना के तहत'' ''

बारे में कहती है उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा, इसमें आवश्यकता के रूप में ''अधिवास'' का उल्लेख नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि संविधान-निर्माताओं ने यह सोचा हो कि उन व्यक्तियों के मामले में जिनका

जन्म अब भारत में हुआ है या जिनके माता-पिता में से किसी का जन्म उस समय में हुआ है जो अब भारत में है, साथ ही ऐसे व्यक्ति के मामले में भी जो लंबे समय से यहां रह रहा है? वर्तमान भारत में पाँच वर्ष से कम समय में, नागरिकता प्रदान करने से पहले अधिवास पर जोर देना आवश्यक था, यह उन व्यक्तियों के मामले में आवश्यक नहीं था जिनके माता-पिता या जिनके दादा-दादी का जन्म पहले भारत में हुआ था, लेकिन अब भारत में नहीं है। हमारी राय में संविधान निर्माताओं ने ऐसा नहीं सोचा होगा। वे जानते थे कि दुनिया के लगभग सभी देशों में नागरिकता के लिए जन्म या निवास स्थान को एक आवश्यक शर्त के रूप में मानने का सामान्य नियम था। वे जानते थे कि कुछ इसी तरह की समस्या से निपटने के लिए, जो उस समय आयरिश फ्री स्टेट के क्षेत्र से पैदा हुए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में थी, आयरिश फ्री स्टेट के संविधान ने भी नागरिकता की आवश्यकता के रूप में आयरिश फ्री स्टेट में अधिवास पर जोर दिया था। उन व्यक्तियों के संबंध में, जो वर्तमान भारत के बाहर पैदा हुए थे, या जिनके माता-पिता या दादा-दादी का जन्म वहां हुआ था, यहां उनके द्वारा इसी तरह का आग्रह न करने का कोई संभावित कारण नहीं हो सकता है। उन जिज्ञासु परिणामों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए जो इस दृष्टिकोण से होंगे कि भारत के क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने का इरादा आवश्यक रूप से अनुच्छेद 6 में नहीं है। दो व्यक्तियों का मामला लें, जिनमें से एक का जन्म वर्तमान भारत में हुआ

था और वह हमेशा से वहीं रहा है और एक अन्य व्यक्ति जो वर्तमान भारत में पैदा हुआ था, वह अब पाकिस्तान के क्षेत्रों में रहने चला गया और फिर वापस उसी क्षेत्र में चला गया, जो अब भारत है। पहले नामित व्यक्ति को नागरिक होने से पहले संविधान के प्रारंभ में अधिवास की आवश्यकता को पूरा करना होगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति को यह शर्त पूरी नहीं करनी होगी। यह सोचना अनुचित होगा कि संविधान-निर्माताओं द्वारा ऐसे विचित्र परिणाम की कल्पना की गई होगी।

इन सभी कारणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब संविधान निर्माताओं ने ''भारत के क्षेत्र में प्रवासित'' शब्दों का प्रयोग किया तो उनका अर्थ था ''भारत के क्षेत्र में स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से आये'' । अनुच्छेद 6 में ''उनके स्पष्ट रूप से ''अधिवास'' या ''स्थायी रूप से निवास करने के इराद'' का उल्लेख नहीं करने का एक मात्र स्पष्टीकरण है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें विश्वास था कि इस संविधान की योजना में ''मैं प्रवासन'' शब्द का अर्थ केवल ''वहां स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से देश में आना'' के रूप में किया जा सकता है। इस संबंध में अनुच्छेद 7 के परंतुक पर ध्यान देना दिलचस्प है। वह अनुच्छेद अपने पहले भाग में प्रावधान करता है कि जो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा या अनुच्छेद 5 और 6 में भारत का नागरिक माना जाएगा। उस व्यक्ति को नागरिक नहीं

माना जाएगा यदि वह 1 मार्च 1947 के बाद उस क्षेत्र से पाकिस्तान चले गए हैं। परंतुक ऐसे कुछ व्यक्तियों से संबंधित है जो पाकिस्तान में इस

तरह के प्रवास के बाद भारत लौट आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जब यह रिटर्न पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत होता है- यानी, भारत में पुनर्वास या यहां स्थायी रूप से निवास करने के इरादे से भारत लौटना- तो अनुच्छेद 7 के मुख्य प्रावधान लागू नहीं होंगे और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार ऐसे व्यक्ति को 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में प्रवासित माना जाएगा। ऐसे प्रवासी की भारत वापसी पुनर्वास या स्थायी वापसी के परमिट के तहत होनी चाहिए ताकि वह नुकसान से बच सके। अनुच्छेद 6 में ऐसा सोचने के लिए नागरिकता एक मजबूत कारण है। भारत में स्थायी रूप से निवास करने का इरादा ''मैं भारत के क्षेत्र में स्थानांतरित हो गया'' वाक्यांश के उपयोग में निहित है।

कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक देश से दूसरे देश में जाता है, तो स्थानांतरण के समय उसका इरादा उस देश में रहने का होता है जहां वह केवल अस्थायी रूप से गया था, लेकिन बाद में उसका इरादा बन जाता है। वहां स्थायी रूप से निवास करने का इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब ऐसा होता है, तो उस व्यक्ति को बाद के समय में ''स्थायी रूप से रहने के इरादे से देश में आया'' माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हालाँकि जिस समय वह नई जगह या नए देश में चला गया, उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह इस जगह या देश में चला गया है, लेकिन कानून के अनुसार उसे बाद में इस स्थान या देश में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उस समय जब वह वहां

स्थायी रूप से रहने का इरादा बनाता है। कानून के इस दृष्टिकोण को चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने अपनाया और हमारे सामने इस पर गंभीरता से विवाद नहीं हुआ।

चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने इस प्रश्न पर उचित ही विचार किया कि क्या 1944 में जब मंगल सेन पहली बार अपने घर झावरियान से जो तब भारत का क्षेत्र है, जालंधर आया था, जो अब पाकिस्तान में है, उसका इरादा भारत में स्थायी रूप से रहने का था और भले ही उस समय उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, चाहे 1944 में जो अब भारत का क्षेत्र है, वहां आने के बाद, उन्होंने बाद में किसी समय यहां स्थायी रूप से रहने का इरादा बनाया था। इस प्रश्न पर, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, चुनाव न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय अलग-अलग निष्कर्ष पर पहुंचे। जबकि चुनाव न्यायाधिकरण ने माना कि मंगल सेन का किसी भी समय भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं था, उच्च न्यायालय यह मानने के लिए तैयार था कि जब वह 1944 में अपने घर से पंजाब के पूर्वी जिलों में चले गए तब भी उनका इरादा था। वहां स्थायी रूप से निवास कर रहे थे, और उनका मानना था कि कम से कम 15 अगस्त, 1947 के बाद, उनका भारत के डोमिनियन को अपना निवास स्थान बनाने और यहां स्थायी रूप से रहने के अलावा कोई अन्य इरादा

नहीं था। हमारे सामने दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया गया है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उच्च न्यायालय ने मनमाने ढंग से काम किया है

और महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रतिवादी का भारत में स्थायी रूप से रहने का कोई इरादा नहीं था। ऐसे तर्क पर विचार करते समय, हमारे लिए इसके प्रावधानों को ध्यान में रखना उचित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 116 बी में कहा गया है कि चुनाव याचिका में चुनाव न्यायाधिकरण के आदेश की अपील पर उच्च न्यायालय का निर्णय ''अंतिम और निर्णायक'' होगा। इस न्यायालय द्वारा एक से अधिक मामलों में यह बताया गया है कि हालांकि ये प्रावधान एक उपयुक्त मामले में उच्च न्यायालय के फैसले में इस न्यायालय के हस्तक्षेप के रास्ते में खड़े हैं, लेकिन हमारे लिए इन प्रावधानों को सहन करना उचित होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ध्यान में रखें, जब इस तरह के निर्णय की सत्यता को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है। हमारे लिए इस पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या उच्च न्यायालय के इस विचार को कि 1944 में भी मंगल सेन को पंजाब के पूर्वी जिलों में स्थानांतरित किया गया, कहा जा सकता है, सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है या नहीं। यह मानते हुए भी कि निष्कर्ष रास्ते से बाहर है, उच्च न्यायालय का आगे का निष्कर्ष यह है कि 1944 में अपने गृह जिले से जालंधर चले जाने के बाद मंगल सेन का 15 अगस्त 1947 के बाद भारत के क्षेत्र को अपना स्थान बनाने के अलावा कोई अन्य इरादा नहीं था। निवास स्थान अब पाकिस्तान से भारत के क्षेत्र में उसके प्रवास को साबित करने के लिए पर्याप्त होगा। हमें इस प्रश्न से

संबंधित रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों से अवगत कराया गया है और हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस बिंदु पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष में हमारे हस्तक्षेप को उचित ठहरा सके। अपीलकर्ता के वकील द्वारा इस तथ्य पर बहुत जोर दिया गया था कि मंगल सेन ने जनवरी, 1950 में बर्मा के लिए भारतीय तट छोड़ दिया था, और उनके वहां पहुंचने के बाद धारा के तहत एक आवेदन किया था। संघ नागरिकता अधिनियम, 1948, (बर्मा के) के 7(1) में देशीयकरण के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के उनके इरादे की सूचना दी गई है और उसमें उनका बयान है कि वह बर्मा संघ के भीतर स्थायी रूप से निवास करने का इरादा रखते हैं। हालाँकि, यह मानते हुए कि अक्टूबर 1950 में, या यहाँ तक कि जनवरी 1950 में, जब वह बर्मा के लिए रवाना हुए, मंगल सेन ने बर्मा में अपना स्थायी निवास लेने का इरादा बना लिया था, यह इस सवाल के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है कि क्या 1947 में उनके पास भारत में स्थायी रूप से निवास करने का इरादा था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने इसी आवेदन में दिए गए एक बयान पर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि मंगल सेन 1947 में अपनी मां के साथ बर्मा लौट आए थे। उच्च न्यायालय ने इस बयान पर विचार करने के बाद माना कि वह 1947 में वापस नहीं आए थे। हमने उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। हमारी राय में, उच्च न्यायालय के फैसले की सत्यता के संबंध में किसी भी संदेह को उचित ठहराने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि

15 अगस्त, 1947 के बाद मंगल सेन, जो पहले पाकिस्तान में एक जगह से भारत में जालंधर चले गए थे, निश्चित रूप से बने थे। उनका मन भारत को अपना स्थायी घर बनाने का था। जनवरी, 1950 में चाहे या नहीं, उन्होंने यह बदल दिया कि इरादा हमारे उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है।

इसलिए हमारा निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय का यह मानना सही है कि मंगल सेन भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 की पहली आवश्यकता को पूरा करता है कि ''अब पाकिस्तान में शामिल क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में प्रवासन'' शामिल है। यह विवादित नहीं है और ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मंगल सेन का जन्म भारत में हुआ था जैसा कि भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, और इस प्रकार वह अनुच्छेद 6 के खण्ड (ए) की आवश्यकता को पूरा करता है।

इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि उनके प्रवास की तारीख, जिसे वर्तमान उद्देश्य के लिए 15 अगस्त, 1947 माना जाता है, के बाद से, मंगल सेन आमतौर पर भारत के क्षेत्र में रह रहे हैं।'' श्री शास्त्री ने तर्क दिया कि संतुष्ट करने के लिए ''प्रवास की तारीख से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होने के परीक्षण में यह दिखाया जाना था कि

मंगल सेन 26 जनवरी, 1950 को भारत में थे। हमें नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता है। सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए संविधान का अनुच्छेद 6 उन अनुच्छेदों में से एक है जो 26 नवंबर, 1949

को लागू हुआ। आवेदन करने के लिए ''अपने प्रवास की तारीख से भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी होने की कसौटी पर विचार करना आवश्यक है। प्रवास की तारीख से 26 नवंबर, 1949 तक की अवधि तथापि यह भी आवश्यक नहीं है कि 26 नवंबर, 1949 को या उस तारीख से ठीक पहले वह भारत के क्षेत्र में रह रहा हो। आवश्यक यह है कि प्रवासन पूर्ण होने की तारीख से शुरू होने वाली और 26 नवंबर, 1949 को समाप्त होने वाली अवधि को समग्र रूप से लेते हुए, व्यक्ति ''भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि इस अवधि के प्रत्येक दिन वह भारत में ही रहे। संविधान में ''सामान्य तौर पर निवासी शब्दों की परिभाषा के अभाव में, इन शब्दों का अर्थ ''बिना किसी गंभीर रुकावट के इस अवधि के दौरान निवासी लेना उचित है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियां इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं कि कम से कम 15 अगस्त, 1947 से 26 नवम्बर, 1949 तक भारत के क्षेत्र में मंगल सेन का निवास था, इसमें कोई तोड़-मरोड़ करने लायक नहीं था।

इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत भारत का नागरिक माने जाने के मंगल सेन के दावे को बरकरार रखने में उच्च न्यायालय सही था और उस दृष्टि से उनकी अपील की

अनुमति देना और चुनाव याचिका को खारिज करने का आदेश देना भी सही था।

हमारे मत में संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत् मंगल सेन के नागरिकता के दावे के संबंध में यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि ''क्या अनुच्छेद 5 के तहत् उसका नागरिकता का दावा भी अच्छा था।

इसलिये हम अपील को खर्चे सहित खारित करते है।

अपील खारिज की गई।

अनुवादक

(दिनेश कुमार शर्मा)

न्यायिक अधिकारी,

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक **दिनेश कुमार शर्मा, न्यायिक अधिकारी** द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।